Court No. - 13

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 7681 of 2024

Applicant :- Mohan Chauhan @ Mohan
Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another
Counsel for Applicant :- Salman Abbas,Syed Waqar Husain
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania,J.

1. Heard counsel for the parties.

2. The present application has been filed with prayer to set-aside/ quashing the order dated 22.07.2024 rejecting the discharge application of the applicant in Crime No. 352/2023, under Sections 147, 148, 149, 452, 427, 323, 308, 307, 504, 506, 379 IPC, Police Station Indira Nagar, Lucknow.

3. Before proceeding further in the matter, it would be apt to indicate that earlier the applicant approached this Court by way of Application u/s 482 No. 5799 of 2024 (Mohan Chauhan @ Mohan Vs. State of U. P. and Another). This application was filed challenging the entire criminal proceedings pending before the trial court arising out of Case Crime No. 352 of 2023, under Section 147, 148, 149, 452, 427, 323, 308, 307, 504, 506, 379 IPC, Police Station Indira Nagar, Lucknow, including charge sheet No. 01/ 2023 dated 28.12.2023 only to the extent of Section 307 and 308 IPC.

4. This Court vide order dated 28.06.2024 declined to interfere in the matter and disposed of the application with liberty to the applicant to prefer an application seeking discharge before the court concerned. This liberty was granted on the request made by the counsel for the applicant. The order dated 28.06.2024 reads as under:

> *"Heard learned counsel for the applicants, Sri Rao Naresh Singh, learned A.G.A.-I for the State and perused the record.*
>
> *The instant application has been filed with prayer to set aside the order summing order dated 02-01-2024 passed in Crime no. 352/2023 U/s- 147, 148, 149, 452, 427, 323, 308, 307, 504, 506, 379 IPC, PS-Indira Nagar, Lucknow as well as the entire criminal proceeding arising out of Crime no. 352/2023 U/s- 147, 148, 149, 452, 427, 323, 308, 307, 504, 506, 379 IPC, PS-Indira Nagar, Lucknow chargesheet no. 1, dated 28-12-2023 only to the extent of section 307, 308 of IPC.*
>
> *Learned counsel appearing for the applicant submits that the applicant was never involved in committing offence and he has been implicated due to ulterior motive. He next added that the nature of injuries are simple and that cannot constitute the offence under section 307 of IPC. He submits that the role of the present applicant is distinguishable from the role of other co-accused persons. He added that the*

criminal proceedings against the present applicant is nothing but harassment.

On the other hand, learned counsel appearing for the State has opposed the contention aforesaid and submits that there is no abuse of process of law and only factual matrix has been agitated before this before this Court and that could not be gone into at this stage, invoking the jurisdiction under Section 482 Cr.P.C. and thus the application is liable to be dismissed.

After the argument at length, learned counsel for the applicant submits that interest of justice would be sub-served, if this Court directs the court below to permit the applicants to appear before the court below and file an application of discharge. He further submits that the court below may be directed to decide the discharge application within stipulated period of time, as may be fixed by this Court.

Learned AGA for the State has no objection to the aforesaid submission.

In view of aforesaid, the applicant is permitted to file an application for discharge before the court below within a period of two weeks from today and if such an application is filed, the same shall be decided within a further period of 30 days, strictly in accordance with law.

With the aforesaid observation, the application is disposed off."

5. Taking benefit of the order dated 28.06.2024, the applicant preferred an application dated 19.07.2024 under Section 227 CrPC seeking discharge. The trial court rejected the said application vide order impugned dated 22.07.2024. The relevant portion of the order dated 22.07.2024 reads as under:-

"पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अंतर्गत धारा - 147, 148, 149, 452, 427, 323, 307, 308, 504, 508, 379 भा०दं०सं० कुल्लन यादव, मोहन चौहान एवं अन्य तथा 30-40 अज्ञात व्यक्तियों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। विवेचक द्वारा अभियुक्त कुल्लन यादव उर्फ अनमोल दास व मोहन चौहान के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। चिकित्सीय आख्या के अनुसार वादी मुकदमा के शरीर पर पायी गयी चोटें साधारण प्रकृति की है, जो कठोर एवं कुंद वस्तु द्वारा कारित की गयी है। धारा 161 के बयानों के अनुसार अभियुक्त व अन्य लोग लोहे की राड, लाठी डण्डों आदि तथा ईंट पत्थर से वादी मुकदमा को मारा माँ, बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ दी व वादी मुकदमा के शरीर पर लोहे की राड से जान से मारने की नियत से वार किया गया तथा अभियुक्त कुल्लन यादव द्वारा सीने पर चढ़कर पैरो से प्रहार किया गया , जिससे उन्हें खून की उल्टियाँ हुई। डॉक्टर के बयान के अनुसार चोटहिल बेहोशी हालत में उपचार हेतु लाये गये थे। इस प्रकार विवेचना में आये साक्ष्य से प्रथम दृष्या प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता प्रकट होती है। उसके द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ लोहे की राड, लाठी डण्डों व ईंट व पत्थर से मारने व जान से मारने की धमकी का अपराध प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।

अभियुक्त की ओर से शिव मनी एवं अन्य बनाम राज्य 2023 आई०एन०एस०सी० 227 रमेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 1992 एस०सी० 664 मेरम भाई, पंजा भाई खाँचा एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 1996 एस०सी० 3236 प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि यह निर्णय के विरूद्ध पारित अपील में निर्णीत है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली अभी आरोप विरचन के स्तर पर है। इस सम्बंध में-

जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सज्जन कुमार बनाम सी०बी०आई० 2010 (9) एस०सी०सी० 368 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचन के स्तर पर या उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय

साक्ष्यों की ग्राहयता, विश्वसनीयता तथा सत्यता का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिये। साक्ष्यों की विश्वसनीयता व सत्यता का परीक्षण विचारण के स्तर पर किया जाना चाहिये

कनार्टक राज्य बनाम लोकायुक्त एम०आर० हिरेमत (2019) एस०सी०सी० 734 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिये कि पत्रावली पर जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से लाये गये हैं वह सत्य हैं और यह देखा जाना चाहिये कि उक्त तथ्यों के आधार पर कथित अपराध गठित होता है या नहीं।

पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह, 2009(3) एस०सी०सी० 850 में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुख्ता सन्देह के आधार पर भी आरोप तय किये जा सकते है। इस स्तर पर सबूतों की जांच और मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिये।

शोराज सिंह अहलावत बनाम स्टेट आंफ उत्तर प्रदेश ए०आई०आर० 2013 एस०सी० 52 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अथवा सामग्री से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, चाहे वह कितना ही सन्देहास्पद क्यों न हो, अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाना चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडू राज्य बनाम जयललिता, ए आई आर 2000 सुप्रीम कोर्ट, 1589 एवं दिल्ली राज्य बनाम ज्ञान देवी, ए आई आर 2001 सुप्रीम कोर्ट 40 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि आरोप विरचना के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य का अवलोकन किया जाएगा। साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण आरोप विरचना के स्तर पर अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को इस स्तर पर विचार में नहीं लिया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त मोहन चौहान के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं और ठोस सन्देह (Strong suspicion) के आधार पर भी आरोप निर्मित किए जाने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लियाकत बनाम उ०प्र० राज्य 2008 (62) ए सी सी 453 (इलाहाबाद) उचित ठहराया गया है।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली में आरोप विरचन हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। इस स्तर पर साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण आपेक्षित नहीं है। अतः अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थी /अभियुक्त मोहन चौहान उर्फ मोहन द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.07.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मोहन चौहान उर्फ मोहन द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-227 दं०प्र०सं० दिनांकित 09.07.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 30.07.2024 को पेश हो।"

6. The order aforesaid has been challenged on the ground that n view of the injuries sustained, offence under Section 307 IPC would not be attracted.

7. Sri Nirmal Kumar Pandey, learned A.G.A. for the State opposed the present application by stating the only on the basis of the nature of injury, it cannot be said that offence under Section 307 IPC is not made out. He also stated that as per various pronouncements of the Hon'ble Apex Court, even in no injury case, punishment indicated under Section 3074 IPC can be awarded and for coming to the conclusion as to whether offence under Section 307 IPC is made out or not, the evidence is required as the FIR cannot be treated as an encyclopedia as has

been held in various pronouncements by the Hon'ble Apex Court. He also stated that as per the allegations levelled against the accused persons, the injured was assaulted with lathi, danda, steel rod and kicks etc though general allegations have been levelled against all the accused.

8. Further submission is that according to the injured witnesses, the applicant was involved in the crime and the testimony of the victim/ injured witness should not be ignored unless compelling circumstances exist. The independent witness also supported the basic story of the prosecution.

9. It is also stated that if after recording of evidence, the trial court would be of the view that if offence under Section 307 IPC is not made out, lesser punishment can be awarded but at this stage, the applicant has no case.

10. On the issue aforesaid, the Hon'ble Apex Court in the judgment passed in the case of **Sivamani v. State, 2023 SCC OnLine SC 1581** observed as under:-

*"...9. The Hon'ble Apex Court in the case of **State of Madhya Pradesh v. Saleem, (2005) 5 SCC 554**, held that to sustain a conviction under Section 307 IPC, it was not necessary that a bodily injury capable of resulting in death should have been inflicted. As such, non-conviction under Section 307, IPC on the premise only that simple injury was inflicted does not follow as a matter of course. In the same judgment, it was pointed out that '…The court has to see whether the act, irrespective of its result, was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in the section.' The position that because a fatal injury was not sustained alone does not dislodge Section 307, IPC conviction has been reiterated in **Jage Ram v State of Haryana, (2015) 11 SCC 366** and **State of Madhya Pradesh v Kanha, (2019) 3 SCC 605**. Yet, in **Jage Ram (supra)** and **Kanha (supra)**, it was observed that while grievous or life-threatening injury was not necessary to maintain a conviction under Section 307, IPC, 'The intention of the accused can be ascertained from the actual injury, if any, as well as from surrounding circumstances. Among other things, the nature of the weapon used and the severity of the blows inflicted can be considered to infer intent.'..."*

11. Upon due consideration of aforesaid, inclusion of observations made by he Hon'ble Apex Court in the judgment(s) referred above and also the fact that earlier the applicants approached this Court on the same grounds for similar reliefs and this Court declined to interfere in the matter as also the statement of the injured witnesses and also that at this stage mini trial is not permissible, this Court finds no force in the present application.

12. In view of the aforesaid, the present application is **dismissed.** No order as to costs.

Order Date :- 31.8.2024
(Manoj K.)

Digitally signed by :-
MANOJ KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench